उत्तम प्रकृति का व्यक्ति क्रोधित होने पर भी भलाई का ही कार्य करता है। जिस प्रकार दूध जो स्वभाव से मीठा होता है, गरम कर देने पर ये और भी स्वादिष्ट हो जाता हैं। –अज्ञात।

वोटर सिर्फ विधायक

बहरहाल, साम, दाम, दंड भेद शुरू से राजनीति के औजार माने जाते रहे हैं। आज की तारीख में भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक आग्रहों के बावजूद राजनीति नैतिकता का पालन करते हुए चलने की आदी नहीं हुई है।

मीना जोशी।।

राष्ट्रपति चुनावों से ऐन पहले राज्यसभा चुनाव नतीजों ने सत्तारूढ़ बीजेपी और इसके सहयोगी दलों का मनोबल और बढ़ाने का काम किया है। राज्यसभा में इस बार खाली हुई सीटों की संख्या तो 57 थी, लेकिन चुनाव सिर्फ चार राज्यों की 16 सीटों के लिए हुए। बाकी 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। मगर बची हुई इन 16 सीटों पर भी चुनाव इतनी शिद्दत से लड़े गए कि लगा ही नहीं यह राज्यसभा का चुनाव है, जिसमें वोटर सिर्फ विधायक होते हैं, जो अमूमन पार्टी लाइन पर ही वोट देते हैं और इसलिए चुनाव नतीजे भी प्रायरू उम्मीदों के अनुरूप ही होते हैं। इस बार इनमें से कोई भी बात सच नहीं हुई। वोटरों को लुभाने और येन केन प्रकारेण प्रभावित करने की कोशिशें इतने जोरों पर थीं कि कोई भी पक्ष अपने विधायकों के विवेक पर भरोसा किए बैठा नहीं रह सका। उन्हें रिसॉर्ट और होटलों में भेजकर लगभग बंधक बनाने का काम दोनों पक्षों ने किया। इसके बावजूद न केवल क्रॉस वोटिंग की शिकायतें आईं बल्कि वोट खराब किए जाने के भी मामले सामने आए। बहरहाल, साम, दाम, दंड भेद शुरू से राजनीति के औजार माने जाते रहे हैं। आज की तारीख में भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक आग्रहों के बावजूद राजनीति नैतिकता का पालन करते हुए चलने की आदी नहीं हुई है।

लिहाजा आश्चर्य नहीं कि जहां राजस्थान में कांग्रेस के कई नेता यह दावा करते खुश हो रहे थे कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, वहीं हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर फाउल प्ले का आरोप सामने आने में भी देर नहीं लगी। इस आरोप–प्रत्यारोप से अलग केवल चुनाव नतीजों की बात करें तो राजस्थान में भले बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की हार को कांग्रेस अपनी उपलब्धि मान ले, हरियाणा में अजय माकन की हार उसके लिए कम बड़ा झटका नहीं है। सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र में सत्ता में होने के बावजूद शिवसेना उम्मीदवार का बीजेपी के हाथों हार जाना एक ऐसी चीज है, जिसे पचाना शिवसेना समर्थकों के लिए भी आसान नहीं होगा। कर्नाटक में भी तीन सीटें जीतकर बीजेपी संतोषजनक स्थिति में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी शुरू से राज्यसभा चुनावों को लेकर आक्रामक मुद्रा में रही। उसी ने अतिरिक्त प्रत्याशियों के जरिए चुनावी मुकाबले सुनिश्चित करवाए। चुनावों के दौरान उसकी रणनीति भी ज्यादा चुस्त दुरुस्त रही। विपक्षी खेमे में कई जगहों पर आपसी तालमेल की कमी नजर आई। यही वजह रही कि बीजेपी चार में से तीन राज्यों में अपने अतिरिक्त उम्मीदवार जिताने में सफल हुई। चुनावों से पहले माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार राज्यसभा की 20 सीटें ही बचा पाएगी। मगर वह अपने 22 प्रत्याशियों के साथ–साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने में सफल रही। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जुटे पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इन चुनावों के अनुभव में सीखने को बहुत कुछ है।

हरा–भरा

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

राजा ने फिर से सभी पुत्रों बुलाया और उनसे पेड़ के बारे में पूछा। पहले पुत्र ने पेड़ को बिलकुल सूखा हुआ बताया। दूसरे पुत्र ने पेड़ को हरा–भरा लेकिन फलों से रहित बताया। तीसरे पुत्र ने पेड़ को हरा–भरा और और फलों से लदा हुआ बताया। इसके बाद तीनो पुत्र खुद को सही साबित करने के लिए लड़ने लगे। तभी राजा ने तीनों को रोका और बोला कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम तीनों अपनी जगह सही हो। मैंने तुम तीनों को अलग–अलग मौसम में पेड़ खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वह मौसम के अनुसार था। इससे मैं तुम्हे सीख देना चाहता हूँ। पहली यह कि सही जानकारी के लिए किसी चीज को लम्बे समय तक देखो–परखो। दूसरी यह कि मौसम की तरह ही वक्त भी एक सा नहीं रहता। अतः धैर्य रखो।

संपादकीय

कुशल सिविल सेवा

यह बात स्वीकार करनी होगी कि सरकारी नौकरियों की चमक फीकी पड़ गई है। हमें टैलंट को सरकार की ओर आकर्षित करने की जरूरत है। पेंशन और लाभों की लागत कम करने या उससे बचने के बजाय इसे अपेक्षित शक्ल देनी होगी। हमारी सार्वजनिक सेवाओं में ज्यादातर डॉक्टरों, शिक्षकों, इंजीनियरों और कुछ डेटा क्लर्कों की आवश्यकता होती है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा समर्थित सुधार हमारा प्रारंभिक कदम होना चाहिए। हमें संविदात्मक रोजगार का विस्तार करने के बजाय सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना चाहिए। पिछले कुछ दशकों से हम सार्वजनिक वस्तुओं में कम निवेश कर रहे हैं। कोविड संकट के दौरान यह साफ दिखा कि महामारी को तो छोड़ दें, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था के पास सामान्य परिस्थितियों में भी नागरिकों को पर्याप्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की क्षमता नहीं है। सार्वजनिक सेवा प्रावधान के विस्तार से कुशल श्रम के साथ अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों का सृजन भी होगा, जो हमें सामाजिक स्थिरता प्रदान करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने पर जोर देने से सामाजिक संपत्ति का निर्माण होगा। इससे आयुष्मान भारत जैसे बीमा–आधारित मॉडल के भी कारगर होने में मदद मिलेगी। इस तरह के खर्च से अंततः उपभोक्ता मांग में वृद्धि के साथ कई और ठोस प्रभाव सामने आएंगे। यह कुशल सिविल सेवा के लिए क्षमता निर्माण का समय है। कभी 'जय जवान, जय किसान' सरकार के लिए प्रेरक आदर्श था। आज तो इस मूल्य को खारिज करना ही आदर्श हो गया है।

हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर जनवरी 2022 में रेलवे के डिब्बे फूंक दिए। एक संविदाकर्मी के लिए सम्मान के साथ राष्ट्र की सेवा करना, उसके बुनियादी हक और सरोकार से जुड़ा मसला है।

स्वास्थ्यकर्मियों को झटका

वरुण गांधी।।

साल 2019 में हर घंटे एक भारतीय नागरिक ने बेरोजगारी, गरीबी या दिवालिएपन के कारण खुदकुशी की। तकरीबन 25 हजार भारतीय 2018 से 2020 के बीच बेरोजगारी या कर्ज में डूबे होने के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हुए। जो लोग अब भी बेरोजगार हैं, उनके लिए विरोध प्रदर्शन एक स्वाभाविक नियति है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित खामियों को लेकर जनवरी 2022 में रेलवे के डिब्बे फूंक दिए। एक संविदाकर्मी के लिए सम्मान के साथ राष्ट्र की सेवा करना, उसके बुनियादी हक और सरोकार से जुड़ा मसला है। इसकी अवहेलना की स्थिति में हाल में हमने अग्निवीर योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उबलते देखा है।

सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी स्थिति खास बेहतर नहीं है। मई, 2022 में हरियाणा में 2,212 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं एक झटके में समाप्त हो गईं। जो लोग एकबारगी सड़क पर आए, उनमें नर्स, सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इन लोगों को कोविड महामारी के दौरान काम पर रखा गया था, लेकिन बाद में उनकी जरूरत महसूस नहीं की गई। 'इस्तेमाल करो और फेंको' का यह क्लासिक उदाहरण है।

शॉर्ट नोटिस पर लोगों को रखना और उन्हें

हटाना हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे बाहर से आयात किया गया है। इस आयातित संस्कृति के कारण असम में 8,300 पंचायत और ग्रामीण विकास संविदाकर्मियों ने फरवरी 2022 में विरोध प्रदर्शन किया। वे 12–14 वर्षों से अनुबंध पर थे और उन्हें बोनस, भत्ते, पेंशन या वेतन संशोधन नहीं दिए गए थे। इसी तरह अप्रैल, 2022 में छत्तीसगढ़ के राज्य बिजली विभाग के 200 संविदाकर्मियों पर पहले पानी की बौछार की गई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक लोक सेवक के लिए ऐसी सूरत का सामना करना कितना त्रासद है, बताने की जरूरत नहीं।

दरअसल, इस पूरे मामले में समस्या दोहरी है। पहली बात तो यह कि सरकार में खाली पदों को पर्याप्त गति से नहीं भरा जा रहा। जुलाई, 2021 में सभी स्तरों पर सरकार में 60 लाख से अधिक रिक्तियां थीं। इनमें से 9,10,513 रिक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में थीं, जबकि पीएसयू बैंकों में दो लाख रिक्तियां होने का अनुमान था। इसके अलावा राज्य पुलिस में 5,31,737 से अधिक रिक्तियां और प्राथमिक विद्यालयों में 837,592 पद खाली होने का अनुमान था। सरकार ने 1.5 वर्षों में मिशन–मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की बात कही है। हालांकि, यह समस्या के आकार से कम होगा। हमें इस मोर्चे पर ज्यादा गंभीर पहल करनी होगी।

दूसरे, जहां रिक्तियों भरी भी जा रही हैं, वे ज्यादातर संविदा के आधार पर ही हैं। 2014 में 43 फीसदी सरकारी कर्मचारियों की नौकरी अस्थायी या संविदा पर थी। 2018 आते–आते इस श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की संख्या 59 फीसदी तक पहुंच गई। मार्च 2020 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए संविदात्मक (और गैर–स्थायी) कर्मचारियों का आंकड़ा 498,807 तक पहुंच गया। फीसदी में यह बढ़त 19 से बढ़कर बढ़कर 37 फीसदी के रूप में सामने आया। इस दौरान स्थायी कर्मचारियों की हिस्सेदारी 25 फीसदी गिरी। 2020 में, जब महामारी के कारण बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रुप बी और सी कर्मचारियों के लिए भर्ती में संशोधन करने की मांग की। पांच साल की अवधि के लिए संविदात्मक रोजगार बढ़ाने की इस पहल में कर्मचारियों को भत्ते और विशिष्ट लाभ की पेशकश नहीं की गई।

सूडोकु नवताल-5326

सरल

5	9		1		2		3	8
			4		5			
2								5
		3		5		4	8	
	7						1	
	5	8		6		9		
8								1
			2		9			
3	4		6		7		5	2

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5325 का हल

4	6	2	3	5	8	9	1	7
8	1	7	9	2	6	3	5	4
3	5	9	1	7	4	6	2	8
6	4	1	5	3	7	2	8	9
2	7	5	8	4	9	6	3	1
9	3	8	2	6	1	4	7	5
1	2	3	6	9	5	7	4	8
5	9	4	7	8	2	1	6	3
7	8	6	4	1	3	5	9	2

अपना ब्लॉग

कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा

मोहन। गौरतलब है कि 2020 में यूपी में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 9 लाख थी। इस व्यवस्था के तहत पांच साल की अवधि के बाद नियमितीकरण की भी बात कही गई। अलबत्ता इसके लिए एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जो इस प्रक्रिया में पास नहीं होंगे, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। मृत कर्मचारी के किसी भी आश्रित को यदि ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे भी इसी तरह के मूल्यांकन से गुजरना होगा।

इसी तरह अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी अपशिष्ट जल उपचार क्षमता के विस्तार की महत्वपूर्ण गुंजाइश है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिससे हरित रोजगार पैदा होगा। इसके अलावा, हमें पर्माकल्चर, बागवानी और नर्सरी प्रबंधन में महत्वपूर्ण रोजगार क्षमता के साथ शहरी खेती को प्रोत्साहित करना जारी रखना चाहिए।